आइआइटी में होगा लघु उद्यमियों का समागम

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू में तीन दिनों तक लघु उद्यमियों का समागम होगा। पहले दिन 31 अगस्त को कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट एवं कृषि उत्पाद इकाइयों से संवाद किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन एक सितंबर को लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रतिनिधियों एवं तीसरे दिन दो सितंबर को सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों से संवाद स्थापित किया जाएगा।

यह जानकारी बुधवार को समिति कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में संस्थान के निदेशक प्रो. पीके जैन, मालवीय उद्यमिता एवं संवर्धन केंद्र के समन्वयक प्रो. पीके मिश्र व प्रो. पीके श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से आइआइटी समाज से जुड़ने की कड़ी में आगे बढ़ेगा। निदेशक प्रो. जैन ने बताया कि अब समय आया गया है कि आइआइटी की ब्रांडिंग की जाएं। इसके लिए जरूरी है कि छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को जोड़कर उनको तकनीकी मदद की जाए। बताया कि उद्योग समाज के संगम के बाद इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर समाधान की भी पहल की जाएगी। साथ ही बताया कि अब शहर की सड़कों की दशा को लेकर भी तत्काल रिसर्च किया जाएगा। टूटी सड़कों या किसी हादसे पर जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी से भी बात की जाएगी।

आइआइटी बनाएगा शहर के कचड़े से मेथेनॉल

आइआइटी, बीएचयू में प्रेसवार्ता करते निदेशक प्रो. पीके जैन, प्रो. पीके मिश्र व प्रो. पीके श्रीवास्तव

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू के विशेषज्ञ शहर के कचड़े से मेथेनॉल बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मेथेनॉल पेट्रोल का विकल्प बन सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रो. पीके मिश्र ने बुधवार को पत्रकार वार्ता से इतर बताया कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं जैविक ऊर्जा बोर्ड वाराणसी एवं गोरखपुर में प्लांट स्थापित करेगा। प्रो. मिश्र ने बताया कि प्लांट स्थापित करने के लिए नीति आयोग में बैठक भी हो चुकी है। इसमें पेट्रोल में 15 प्रतिशत तक मेथेनॉल के उपयोग की स्वीकृति मिल चुकी है। फिलहाल पांच प्रतिशत तक मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि भविष्य में मेथेनॉल का प्रयोग 85 प्रतिशत किया किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए देश में जगह-जगह प्लांट स्थापित किए जाने हैं। वाराणसी में प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने की जिम्मेदारी आइआइटी को मिली है। इसको तीन स्तर पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 50 करोड़ राशि मुहैया कराने पर विचार चल रहा है। इस काम में पुणे स्थित नेशनल केमिकल लेबोरेटरी भी सहयोग करेगा।

दैनिक जागरण – 30.08.2018